नंबर है 9518 और "भार सिंचाई क्षेत्र समीक्षा" शीर्षक की नाम की इस रिपोर्ट में भारत सरकार को कृषि क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं ।

महोदय, इस रिपोर्ट में भारत सरकार से कहा गया है कि वह सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को समाप्त कर दे यानि अब सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को बंद करना पड़ेगा । इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिंचाई के लिए बिजली में सबसिडी समाप्त करनी होगी, पानी और बिजली की दरों में भी वृद्धि करनी होगी। इतना ही नहीं, विश्व बैंक ने भारत सरकार को इन परिवर्तनों के लिए 12 महीने का अल्टीमेटम दिया है ।

महोदय, यह रिपोर्ट विश्व बैंक के भारतीय विभाग के कृषि आपरेशन डिवीज़न ने तैयार की है । जो सबसे चिन्ताजनक बात है, वह यह है कि इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने भी हरी झंडी दिखा दी है क्योंकि इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उक्त रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मत्रालय का पूरा सहयोग था । हाल ही में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक के निर्देशों पर धीरे धीरे अमल के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति के अनुरूप ही हमारी कृषि नीति का भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

गाट वार्ताओं के उरुग्वे चक्र में जिन मुद्दों पर बातचीत चल रही थी, उनमें कृषि क्षेत्र भी प्रमुख क्षेत्र था और विकसित देशों द्वारा लगातार भारत जैसे विकासशील देशों पर यह दबाव डालने की कोशिश की जाती रही है कि इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लिए तमाम बाधाओं को दूर किया जाए और कृषि क्षेत्र को भी उनके खुले मुनाफे के लिए छोड़ दिया जाये । विश्व बैंक की यह रिपोर्ट उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है ।

यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है । मैं चाहूंगी कि अखबारों में छपी न खबरों के बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और यह बताये कि इन खबरों में सच्चाई है या नहीं ।

अगर यह खबर सच है तो सदन को यह बताया जाये कि विश्व बैंक की इस कथित रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे कृषि मंत्रालय ने किस प्रकार सहयोग किया था तथा इस रिपोर्ट में जो कुछ छपा था, सरकार को उससे अधिक कोई सूचना है तो वह भी दी जाये ।

सरकार यह बताये कि क्या हमारा कृषि मंत्रालय विश्व बैंक की मदद से अपनी कोई भावी योजना तैयार कर रहा है । अगर यह सही है तो विश्व बैंक के इस गोपनीय सर्कुलर में कहीं गई बातों को सरकार किस हद तक स्वीकार कर रही है और किस मुद्दे पर उसकी सहमति नहीं है ?

यह बहुत ही भयावह स्थिति है । इस बारे में सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए कि हमारे देश की कृषि नीति, हमारी कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है उस बुनियाद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जायेगा और हमारी कृषि नीति के साथ दबाव में आकर कोई कूट नीति नहीं अपनाई जायेगी । क्योंकि अगर इस क्षेत्र को भी हमने उनके लिए खुला छोड़ दिया तो देश की सार्वभौमिकता और देश की स्वतंत्रता की स्थिति क्या होगी यह हमारे देशवासी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार निश्चित रूप में बहुत जल्दी ही इस सदन को अपने विश्वास में ले और मैं सदन से भी मांग करूंगी कि वह सरकार से यह मांग करें कि वह इस संबंध में बयान दे ।

**Problems being faced by New Cooperative Sugar Factories in Maharashtra**

SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, through you, I want

[Shri Viswasrao Ramrao Patil]

like to raise a very vital issue, and that is about the problems of the new cooperative sugar factories to be set up in Maharashtra State.

Sir, the Government of India have issued letters of intent to 38 new sugar actories in Maharashtra State two years back. Out of these, the erection work of nine factories is in progress and they are likely to be commissioned in the later half of 1992-93. The project cost of these factories is around Rs. 27 crores each. The finance for the project is to be raised by way of loan and share capital in the proportion of 60:40. The share capital component is to be raised by the cane grower members and the State Government in the ratio of 1:4:33. As on 22nd JaJnuary, 1992, the State Government has contributed share capital to the extent of Rs. 43.83 crores to these 9 actories. Sir, out of the remaining 29 new factories, 27 factories have been permitted to book orders for purchase of machinery. However, the project cost of these factories has gone up to around Rs. 34 crores. It has, therefore, become necessary to get the viabiltiy of these projects examined once again. The Government of India have appointed a committee to take a review for reducing the project cost. Unless the projects are viable, the financing institutions are not likely to sanction long-term loans to these factories. The State Government has, therefore, requested the Government of India to sanction additonal incentives as below:

(a) The Maharashtra State is at present divided into 2 zones for the purpose of levy sugar. Instead of this, the State should be divided into 3 zones;

(b) The new sugar factories located in high recovery zone should be given the concession of 100 per cent free sale sugar for 10 years, the factories falling in medium recovery zone be given this concession for 12 years, and the low recovery zone should be given this concession for 15 years.

Sir, there is also the participation of the NCDC in the project of new sugar factories. However, due to paucity of adequate funds, it has not yet been possible for the NCDC to sanction financial assistance towards the projects of new sugar factories. The State Government has requested the Government of India to provide additional funds to the NCDC so as to enable it to sanction assistance to sugar factories. Similarly, the central financing institutions should also make adequate provisions for giving financial assistance to these projects.

[**The Vice-Chairman, (Shri Shankar Dayal Singh)** in the Chair]

Sir, the expenditure incurred on harvesting and transportation of sugar cane is not taken into account while fixing the levy price. In Maharashtra State, the harvesting and transportation of sugarcane is the responsibility of the sugar factories. The State Government has therefore, requested the Government of India that the expenditure on these two items should also be taken into account while fixing the levy price of sugar.

In respect of the above proposals, the ex. Chief Minister had written two letters both dated 8th January 1991 to the then Prime Minister.

In order to ensure that the 27 new projects are completed as early as possible and in order to avoid further escalation in the cost of these units, it is absolutely necessary that the above issues are resolved at the earliest.

In the end I request the Food and Civil Supplies Minister, Government of India, to resolve this problem as soon as possible.

With these words, I conclude.